

[2016] 8 एस.सी.आर. 815

अशोक कुमार एवं एएनआर

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 9092 ऑफ 2012)

21 अक्टूबर 2016

[टी. एस. ठाकुर, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.जे.]

सेवा कानून: बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी) (संशोधन) नियम, 2001 -आरआर.5,6, 7, 10 - चयन के माध्यम से पदोन्नति - चयन मानदंड - लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक और इसके लिए पंद्रह अंक साक्षात्कार - चयन सूची को मंजूरी नहीं दी गई, 90:10 के अनुपात में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अंकों के स्थान के साथ नई चयन प्रक्रिया - अपीलकर्ताओं ने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन असफल रहे और बाद में, उन्होंने चयन प्रक्रिया को चुनौती दी - औचित्य - माना गया: अपीलकर्ता चयन की प्रक्रिया पर बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में शामिल हुए - वे बाद में पलट कर यह तर्क नहीं दे सकते कि चयन प्रक्रिया अनुचित थी या उसमें कोई खामी थी, केवल इसलिए कि परिणाम सुखद नहीं था - रोक का सिद्धांत लागू होगा - संविधान भारत की -कला. 309-विबंध का सिद्धांत.

सिविल कोर्ट के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों में से तृतीयवर्गीय पदों पर प्रोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये थे. लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक निर्धारित किये गये थे। नियुक्ति समिति ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची हाईकोर्ट को सौंपी. उच्च न्यायालय ने चयन सूची को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और एक संचार जारी किया जिसमें नब्बे अंकों की नई लिखित परीक्षा आयोजित करने और साक्षात्कार के लिए अक्सर अंक दिए जाने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ताओं ने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया लेकिन असफल रहे और बाद में, उन्होंने चयन प्रक्रिया को चुनौती दी।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

माना गया: 1. अपीलकर्ताओं ने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया। यदि अपीलकर्ता नई प्रक्रिया आयोजित करने के निर्णय से व्यथित थे, तो उन्होंने अपना समाधान नहीं सुझाया। इसके बजाय, उन्होंने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने पर ही उन्होंने रिट याचिका में परिणाम को चुनौती दी। यह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं के लिए खुला नहीं था। एस्टोपेल का सिद्धांत कार्य करेगा। वर्तमान मामले में, तथ्य यह है कि जब नई चयन प्रक्रिया हुई तो अपीलकर्ताओं को स्पष्ट रूप से पता था कि लिखित परीक्षा नब्बे अंक की होगी और साक्षात्कार दस अंक का होगा। अपीलकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इसके अलावा, दो अन्य विचार संतुलन में हैं। इस बारे में अस्पष्टता का एक तत्व था कि क्या नियम 6, जो पदोन्नति से संबंधित था, में केवल तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियम 5 में प्रदान की गई परीक्षा की आवश्यकता को शामिल किया गया था या क्या अंक और योग्यता अंक भी शामिल किए गए थे। इसके अलावा, 90:10 कॉललोकेशन के कारण अपीलकर्ताओं पर कोई पूर्वाग्रह स्थापित नहीं हुआ। [पैरा 11,13]

2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यह निर्देशित किया गया था कि यदि कोई मौजूदा रिक्ति है, तो अपीलकर्ता को तृतीय श्रेणी के पद पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है, जिस पर वह वर्तमान में काम कर रहा है। चयन प्रक्रिया का अगला दौर होने तक अनंतिम आधार। अपीलकर्ता भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि उसे सफल घोषित किया जाता है, तो वह उसके द्वारा खर्च की गई अवधि पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा। वरिष्ठता निर्धारण हेतु तृतीय श्रेणी पद। [पैरा 16]

राज कुमार बनाम शक्ति राज (1997) 9 एससीसी 527 प्रतिष्ठित।

मरिपति नागराजा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2007) 11 एससीसी 522: 2007 (11) एससीआर 506; *धनंजय मलिक बनाम उत्तरांचल राज्य* (2008) 3 पीएलजेआर (एससी) 271; *अम्लान ज्योति बोररूआ बनाम असम राज्य* (2009) 3 एससीसी 227: 2009 (1) एससीआर 593; *चंद्र प्रकाश त्रवारी बनाम शकुंतला शुक्ला* (2002) 6 एससीसी 127: 2002 (3) एससीआर 948; *भारत संघ बनाम एस. विनोद कुमार* (2007) 8 एससीसी 100: 2007 (10) एससीआर 41; *मुनींद्र कुमार बनाम राजीव गोविल* (1991) 3 एससीसी 368: 1991 (2) एससीआर 812; *रश्मि मिश्रा ली म.प्र.*

लोक सेवा आयोग (2006) 12 सेकंड 724 : 2006 (7) पूरक। एससीआर 708; मनीष कुमार शाह बनाम बिहार राज्य (2010) 12 एससीसी 576; विजेंद्र कुमार वर्मा बनाम लोक सेवा आयोग (2011) 1 एससीसी 150: 2010 (12) एससीआर 944; रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी (2013) 11 एससीसी 309: 2013 (5) एससीआर 687; चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जैस्मीन कौर (2014) 10 एससीसी 521: 2014 (9) एससीआर 1122; प्रदीप कुमार रायव. दिनेश कुमार पांडे (2015) 11 एससीसी 493: 2015 (6) एससीआर 825; मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट बनाम एस.के. शिव सुब्रमण्यम (2016) 1 एससीसी 454 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

2007 (11) एससीआर 506	पैरा 7	को संदर्भित करता है
(2008) 3 पीएलजेआर (एससी) 271	पैरा 7	को संदर्भित करता है
2009 (1) एससीआर 593	पैरा 7	को संदर्भित करता है
2002 (3) एससीआर 948	पैरा 12	को संदर्भित करता है
2007 (10) एससीआर 41	पैरा 12	को संदर्भित करता है
1991 (2)) एससीआर 812	पैरा 12	को संदर्भित। करता है
2006 (7) सप्लिमेंट एससीआर 708	पैरा 12	को संदर्भित करता है
(2010) 12 एस सी सी 576	पैरा 12	को संदर्भित करता है
2010 (12) एससीआर 944	पैरा 12	को संदर्भित करता है
2013 (5) एससीआर 687	पैरा 12	को संदर्भित करता है
2014 (9) एससीआर 1122	पैरा 12	को संदर्भित करता है
2015 (6) एससीआर 825	पैरा 12	को संदर्भित करता है
(2016) 1 एस सी सी 454	पैरा 12	को संदर्भित करता है
(1997) 9 एस सी सी एस21	पैरा 14	को प्रतिष्ठित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की सिविल अपील संख्या 9092।

2010 के एलपीए संख्या 1991 में उच्च न्यायालय, पटना के निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.2011 से।

अपीलकर्ता की ओर से अमित पवन, अक्षत श्रीवास्तव, सूर्योदय प्रकाश तिवारी, गौरव सिंह, विज्ञापन बनाम।

नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रेमा सिंह, शशांक सौरव, टी. महिपाल, गोपाल सिंह, श्लोक चंद्र, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ। डी. वाई. चंद्रचूड़, जे, 1 यह अपील 16 दिसंबर 2011 के पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसने नौवें से चौदहवें उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित एक लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति दी थी। डिवीजन बेंच ने 9 नवंबर 2010 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति द्वारा किए गए चयन को रद्द कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने माना है कि मूल याचिकाकर्ता जो पदोन्नति की प्रक्रिया को चुनौती देने में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सफल हुए थे, उन्हें चयन प्रक्रिया में असफल रूप से भाग लेने के कारण ऐसा करने से रोक दिया गया था।

2. 2 दिसंबर 2003 को, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के कार्यालय ने 2003 का सामान्य आदेश संख्या 204 जारी कर मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से छह तृतीय श्रेणी पदों पर पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। चयन नए सिरे से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाना था। 20 अप्रैल 2004 को आयोजित लिखित परीक्षा में सत्ताईस उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिनमें से चौदह उत्तीर्ण हुए। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 7 जुलाई 2004 को हुआ। लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक और साक्षात्कार के लिए 15 अंक निर्धारित थे। नियुक्ति समिति ने तृतीय श्रेणी के छह पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए योग्यता के आधार पर छह अभ्यर्थियों का चयन किया। चयन सूची 26 जुलाई 2004 को उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर चयन सूची को मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि लिखित परीक्षा के लिए आवंटित अंक न्यायालय के 1995 के सामान्य पत्र संख्या 1 के अनुसार नहीं थे और बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ को कवर करने वाले 1992, 1998 और 2001 के नियम। 19 अगस्त 2004 को एक पत्र द्वारा, रजिस्ट्रार (प्रशासन) ने जिला एवं

सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को लिखित परीक्षा के लिए अर्हक अंक पैंतालीस मानते हुए नब्बे अंक निर्धारित करते हुए एक नई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया।

3. तदनुसार, 8 अक्टूबर 2004 को जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा एक नया सामान्य आदेश (2004 का 171) जारी किया गया था। सामान्य आदेश को विशेष रूप से उच्च न्यायालय के 9 अगस्त 2004 के संचार में बदल दिया गया था और निर्धारित किया गया था कि एक नई लिखित परीक्षा जिसमें नब्बे शामिल हों अंक रखे जाएंगे (पैंतालीस के अर्हक अंकों के साथ) जिसके बाद दस अंकों का साक्षात्कार होगा। इसके अनुसरण में, 7 नवंबर 2004 को एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई और उसके बाद 12 दिसंबर 2004 को साक्षात्कार हुआ। परिणाम 31 दिसंबर 2004 को घोषित किए गए और नौवीं से चौदहवीं कक्षा के उत्तरदाताओं को तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया। सभी अपीलकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया।

4. दो अपीलकर्ताओं और चार अन्य असफल उम्मीदवारों ने 8 अक्टूबर 2004 के सामान्य आदेश और 31 दिसंबर 2004 के नियुक्ति आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। प्राथमिक आधार यह था कि नियुक्ति प्रक्रिया दूषित हो गई थी। चूँकि प्रासंगिक नियमों के तहत, लिखित परीक्षा के लिए पचासी अंक और साक्षात्कार के लिए पंद्रह अंक होना आवश्यक था। रिट याचिका के जवाब में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और चयनित उम्मीदवारों द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। प्रशासनिक पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय ने 22 नवंबर 1995 के 1995 (सिविल) के अपने सामान्य पत्र संख्या 1 पर भरोसा करते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव किया, जिसमें नब्बे अंकों (पैंतालीस के अर्हक अंकों के साथ) की एक लिखित परीक्षा निर्धारित की गई थी, जिसके बाद एक परीक्षा आयोजित की गई थी। चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी पदों पर पदोन्नति के लिए साक्षात्कार में दस अंक होंगे। उच्च न्यायालय ने अपने जवाबी हलफनामे में प्रस्तुत किया कि यह सामान्य पत्र क्षेत्र पर कायम है। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी) (संशोधन) नियम, 2001 के नियम 6 में कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक नियुक्ति समिति द्वारा योग्यता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएगी। वरिष्ठता। जबकि 2001 के नियमों में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का तरीका भी निर्धारित किया गया था, पदोन्नति की प्रक्रिया सामान्य पत्र संख्या द्वारा शासित

थी। 1995 का एल। यह आग्रह किया गया था कि 20 दिसंबर 2007 को उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देशों में इसे दोहराया गया है।

5. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ (वर्ग III और वर्ग IV) (संशोधन) नियम, 2001 के नियम 6 के तहत, लिखित परीक्षा में 85 अंक और साक्षात्कार में 15 अंक (इसके स्थान पर) निर्धारित थे। पहले क्रमशः नब्बे अंक और दस अंक की आवश्यकता थी। विद्वान एकल न्यायाधीश की राय में, एक बार नियम, जो अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हैं, 2001 में संशोधित कर दिए गए, तो पहले के नियम खत्म हो जाएंगे और उच्च न्यायालय के सामान्य पत्र में वैधानिकता को खत्म करने का प्रभाव नहीं होगा। नियम। ऐसा माना जाता है कि परीक्षा जुलाई 2001 में नए नियम लागू होने के बाद आयोजित की गई थी। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक और साक्षात्कार के लिए 15 अंक निर्धारित करने वाली अधिसूचना सही ढंग से जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को उन सभी लोगों के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया, जिन्होंने पहली चयन परीक्षा में भाग लिया था।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के बाद, एक निर्देश जारी किया गया जिसके द्वारा 30 नवंबर 2010 को तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त छह व्यक्तियों को उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पदों पर वापस कर दिया गया। उन्होंने चुनौती देने के लिए एक पत्र पेटेंट अपील दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश। इसी बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा प्रथम चयन प्रक्रिया में सफल छह लोगों को तृतीय श्रेणी के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी। उम्मीदवारों में दोनों अपीलकर्ता और चार अन्य उम्मीदवार शामिल थे। पिछले रिजल्ट में भी ये चारों अभ्यर्थी सफल हुए थे। परिणामस्वरूप, दो व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया।

7. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 16 दिसंबर 2011 के एक फैसले और आदेश द्वारा नौवें से चौदहवें उत्तरदाताओं द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को अनुमति दी और, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को रद्द करते हुए, मूल आदेश को बहाल कर दिया। नियुक्ति

दिनांक 31 दिसंबर 2004। डिवीजन बेंच 2001 के नियमों पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रखे गए निर्माण से सहमत थी। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करते हुए, डिवीजन बेंच ने यह विचार किया कि अपीलकर्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन करते हुए बिना किसी विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लिया। चयन प्रक्रिया पर कोई आपत्ति उठाने में विफल रहने पर, यह माना गया कि अपीलकर्ताओं को असफल घोषित होने के बाद चयन को चुनौती देने से रोक दिया गया था। इस दृष्टिकोण को अपनाने में, "1 डिवीजन बेंच ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है: (i) '... ' ओती नागराजा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार'; (ii) धारा; ::;वाई मलिक बनाम उत्तरांचल राज्य और (iii) अमलान ज्योति बोररु बनाम. असम राज्य3•

8. अब शुरुआत में, बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी) (संशोधन) नियमावली, 1998 के प्रावधानों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। नियम 6 में कक्षा 1 कर्मचारियों की भर्ती के तरीके का प्रावधान है। केंद्रीकृत लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार। नियम 6(ii) में पहले प्रावधान था कि लिखित परीक्षा में नब्बे अंक होंगे जबकि साक्षात्कार के लिए दस अंक आवंटित किए जाएंगे। नियम 7 पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से संबंधित है। नियम 7(i) में प्रावधान है कि तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदोन्नति पर नियुक्ति नियुक्ति समिति द्वारा योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। नियम 7(iii) निम्नलिखित शब्दों में है:

"पूर्ववर्ती नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए, नियुक्ति समिति पात्र उम्मीदवारों की एक अलग परीक्षा आयोजित करेगी और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जो लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त करेंगे।"

9. बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी) (संशोधन) नियम, 2001 को 1 जुलाई 2001 से अधिसूचित किया गया था। नियम 5 से 12 प्रतिस्थापित किए गए थे। नियम एस(iv) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के तरीके को नियंत्रित करता है। नियम एस(iv)(डी) में पचासी अंकों की लिखित परीक्षा और पंद्रह अंकों के साक्षात्कार का प्रावधान है, जो कुल मिलाकर एक सौ अंक होता है। लिखित परीक्षा के लिए अर्हक अंक पैंतालीस होने चाहिए। नियम 6 निम्नलिखित शर्तों में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान करता है:

"पदोन्नति द्वारा नियुक्ति- (i) चतुर्थ श्रेणी पदों से पदोन्नति द्वारा तृतीय श्रेणी पदों पर नियुक्तियाँ भी नियुक्ति समिति द्वारा योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जाएंगी;

(ii) तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों का बीस प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से पदोन्नति के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है और उनके पास पद पर तीन वर्ष का अनुभव है;

(iii) पूर्ववर्ती नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए, नियुक्ति समिति पात्र उम्मीदवारों की एक अलग परीक्षा आयोजित करेगी और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जिन्होंने लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त किए हैं।

नियम 7(iv) के तहत, सभी नियुक्तियाँ ऐसे निर्देशों के अधीन हैं जो समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नियम 10 उच्च न्यायालय को समय-समय पर सामान्य या विशेष निर्देश जारी करके नियमों को अर्हता प्राप्त करने या पूरक करने में सक्षम बनाता है। 2001 के संशोधित नियम, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियम एस (iv) में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती और नियम 6 में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति प्रदान करता है। नियम 6 (iii) यह निर्धारित करता है कि पदोन्नति के लिए पूर्ववर्ती नियम के अनुसार, नियुक्ति समिति योग्य उम्मीदवारों की एक अलग परीक्षा आयोजित करेगी और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जो लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त करेंगे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि परिणामस्वरूप, नियम 6 में वह आवश्यकता शामिल है जो लिखित परीक्षा के नियम 5 में प्रदान की गई है जिसमें अस्सी पांच अंक, पंद्रह अंकों का साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में पैंतालीस अंकों के अर्हक अंक शामिल हैं। डिवीजन बेंच ने नियम, 2001 के नियम 5 और 6 के प्रावधानों पर गौर करते हुए पाया कि नियमों की अस्पष्टता के कारण व्याख्या की कुछ गुंजाइश थी। हालाँकि, शेष राशि पर, डिवीजन बेंच नियमों की व्याख्या पर विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं थी।

10. डिवीजन बेंच द्वारा संबोधित मूल मुद्दा यह था कि चयन के नए दौर में भाग लेने वाले अपीलकर्ताओं को असफल घोषित होने के बाद प्रक्रिया पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस पहलू पर, तथ्यों का संक्षिप्त पुनर्कथन उचित होगा। चयन की मूल प्रक्रिया में, 2 दिसंबर 2003 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर द्वारा 2003 के सामान्य आदेश

संख्या 204 जारी करने के बाद, 20 अप्रैल 2004 को 85 अंकों की एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद 7 जुलाई को साक्षात्कार हुआ। 2004 में पंद्रह अंक शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने चयन सूची को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और अपने रजिस्ट्रार (प्रशासन) के माध्यम से 19 अगस्त 2004 को एक पत्र जारी किया, जिसमें नब्बे अंकों वाली एक नई लिखित परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता थी, जिसमें अर्हक अंक पैंतालीस माने जाएंगे। इसका सामान्य पत्र क्रमांक 1 of 1995. इसके अनुसरण में, 8 अक्टूबर 2004 को एक नए सामान्य आदेश: आर ईयरिंग नंबर 171 ऑफ 2004 के रूप में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 19 अगस्त 2004 को उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में एक नई लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। नब्बे अंक (अर्हता अंक पैंतालीस के साथ) के बाद साक्षात्कार के बाद अक्सर अंक दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं थी।

11. अपीलकर्ताओं ने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया। यदि अपीलकर्ता नई प्रक्रिया आयोजित करने के निर्णय से व्यथित थे, तो उन्होंने अपना समाधान नहीं सुझाया। इसके बजाय, उन्होंने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने पर ही उन्होंने रिट याचिका में परिणाम को चुनौती दी। यह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं के लिए खुला नहीं था। एस्टोपेल का सिद्धांत कार्य करेगा

12. इस न्यायालय के कई निर्णयों में इस विषय पर कानून को स्पष्ट किया गया है। **चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला**⁴ में, इस न्यायालय ने यह सिद्धांत दिया कि जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में शामिल होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है, तो प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जाती है। उस परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता जहां कोई उम्मीदवार उपस्थित हुआ हो और भाग लिया हो। वह बाद में पलट कर यह तर्क नहीं दे सकता कि प्रक्रिया अनुचित थी या उसमें कोई कमी थी, केवल इसलिए कि परिणाम सुखद नहीं है। **भारत संघ बनाम एस. विनोद कुमार**⁵ में इस न्यायालय ने कहा कि:

"18. यह भी अच्छी तरह से तय है कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में निर्धारित 823 प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानते हुए भाग लिया था, वे प्रश्न डी के हकदार नहीं थे ...

(मुनींद्र कुमार बनाम राजीव गोविल⁶ और रश्मी मिश्रा बनाम म.प्र. लोक सेवा आयोग⁷ भी देखें)।"

अमलान ज्योति बोरोआह (सुप्रा) में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया था, जहां यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और उसमें निर्धारित प्रक्रिया को पूरी तरह से जानते हैं, वे असफल घोषित होने पर इस पर सवाल उठाने के हकदार नहीं हैं।

मनीष कुमार शाह बनाम बिहार राज्य⁸ में, निम्नलिखित टिप्पणियों में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था:

"16. हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद यह पूरी तरह से जानते हुए कि मौखिक परीक्षा के लिए 19% से अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं, याचिकाकर्ता चयन के मानदंड या प्रक्रिया को चुनौती देने का हकदार नहीं है। निश्चित रूप से, यदि याचिकाकर्ता का नाम मेरिट सूची में आया होता, तो उसने चयन को चुनौती देने का सपना भी नहीं देखा होता। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल तभी किया जब उसे पता चला कि उसका नाम मेरिट सूची में नहीं है। आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में उसका नाम शामिल है। याचिकाकर्ता का यह आचरण स्पष्ट रूप से उसे चयन पर सवाल उठाने से वंचित करता है और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करके कोई त्रुटि नहीं की है। इस संबंध में निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है मदनलाल बनाम जे. और के. राज्य, MANU/SC/0208/1995: (1995) 3 SCC 486, मरिपति नागराजा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य। MANU/SC/8040/2007: (2007) 11 SCC 522 , धनंजय मलिक और अन्य। उत्तरांचल राज्य और अन्य। MANU/SC/7287/2008: (2008) 4 SCC 171, अमलानज्योतिबरूआ बनाम असम राज्य MANU/SC/ 0077/2009: (2009)3 SCC227 और K.A. नागमणि बनाम इंडियन एयरलाइंस और अन्य। (सुप्रा)।"

विजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम लोक सेवा आयोग⁹, चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को पता था कि उन्हें कंप्यूटर संचालन में कुछ विशिष्ट योग्यताएं रखने की आवश्यकता है। अपीलकर्ता चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुए थे और साक्षात्कार में भाग लेने के बाद चयन प्रक्रिया को अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण चुनौती देने की मांग की थी। इसे अस्वीकार्य माना गया।

रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी¹⁰ में, उत्तराखंड राज्य में फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों ने एक विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया। इस न्यायालय ने माना कि यदि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती, तो उत्तरदाताओं ने चयन प्रक्रिया या अपनाई गई पद्धति पर कोई आपत्ति नहीं जताई होती। चयन का मौका लेने के बाद, यह माना गया कि उत्तरदाताओं को अनुच्छेद 226 के तहत राहत पाने का अधिकार नहीं है और यह माना जाएगा कि उन्होंने विज्ञापन या चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने का अपना अधिकार छोड़ दिया है। इस न्यायालय ने माना कि:

"18. यह स्थापित कानून है कि जो व्यक्ति जानबूझकर चयन की प्रक्रिया में भाग लेता है, वह उसके बाद चयन की विधि और उसके परिणाम पर सवाल नहीं उठा सकता है।"

चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जैस्मीन कौर¹¹ में, यह माना गया था कि एक उम्मीदवार जो खुद को चयन प्रक्रिया के अधीन करके एक परिकल्पित जोखिम या मौका लेता है, वह अपने गैर-चयन के बारे में जानने के बाद शिकायत नहीं कर सकता है कि चयन की प्रक्रिया अनुचित थी। . **प्रदीप कुमार रायव.दिनेश कुमार पांडे**¹² में, इस न्यायालय ने माना कि:

"इसके अलावा, हम एक और बिंदु पर डिवीजन बेंच से सहमत होंगे कि अपीलकर्ताओं ने साक्षात्कार की प्रक्रिया में भाग लिया था और परिणाम घोषित होने तक इसे चुनौती नहीं दी थी। साक्षात्कार और परिणाम की घोषणा के बीच लगभग चार महीने का अंतर था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने उस समय इसे चुनौती नहीं दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल जब अपीलकर्ताओं ने खुद को असफल पाया, तो उन्होंने साक्षात्कार को चुनौती दी। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। उम्मीदवार एक ही समय में अनुमोदन और पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहिए था और प्रक्रिया को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी या उन्हें साक्षात्कार आयोजित होने के तुरंत बाद चुनौती देनी चाहिए थी।"

इस सिद्धांत को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट बनाम एस.के. शिव सुब्रमण्यम¹³•

के हालिया फैसले में दोहराया गया है।

13. वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब नई चयन प्रक्रिया हुई तो अपीलकर्ताओं को स्पष्ट रूप से नोटिस दिया गया था कि लिखित परीक्षा नब्बे अंक

की होगी और साक्षात्कार दस अंक का होगा। अपीलकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इसके अलावा, दो अन्य विचार संतुलन में हैं। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में कहा कि नियम 6 की व्याख्या अस्पष्टता से मुक्त नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई स्पष्ट या पेटेंट अवैधता नहीं थी। इस बारे में अस्पष्टता का एक तत्व था कि क्या नियम 6, जो पदोन्नति से संबंधित था, में केवल तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियम 5 में प्रदान की गई परीक्षा की आवश्यकता को शामिल किया गया था या क्या अंक और योग्यता अंक भी शामिल किए गए थे। इसके अलावा, 90:10 आवंटन के कारण अपीलकर्ताओं पर कोई पूर्वाग्रह स्थापित नहीं हुआ।

14. **राज कुमार बनाम शक्ति राज**¹में फैसला. ~ (जिस पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया था) में एक ऐसा मामला शामिल था जहां सरकार को प्रक्रिया में घोर अवैधताएं करते हुए पाया गया था। इसलिए, यह माना गया कि आचरण या सहमति द्वारा रोक के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं था। निर्णय अलग है।

15. इस मामले को देखते हुए, डिवीजन बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती नहीं कर सकती कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद अपीलकर्ताओं के लिए परिणाम पर सवाल उठाना खुला नहीं था, एक बार उन्हें असफल घोषित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय को सूचित किया गया कि छह में से चार उम्मीदवार, जिन्हें अंततः चुना गया था, चयन की पहली प्रक्रिया के साथ-साथ बाद के चयन में भी शामिल थे। बताया जाता है कि एक उम्मीदवार सेवानिवृत्त हो चुका है।

16. अब आशंका यह है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के परिणामस्वरूप शेष उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। हमारे विचार में, यह उचित होगा यदि इक्विटी को एक उपयुक्त दिशा द्वारा विधिवत समायोजित किया जाए। हमारा विचार है कि न्याय का उद्देश्य इस निर्देश से पूरा होगा कि यदि कोई मौजूदा रिक्ति है, तो अपीलकर्ता जो अभी भी सेवा में बना हुआ है, उसे तृतीय श्रेणी के पद पर काम करना जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। वह वर्तमान में चयन प्रक्रिया का अगला दौर होने तक अनंतिम आधार पर काम कर रहा है। अपीलकर्ता भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि उसे सफल घोषित किया

जाता है, तो वह उसके द्वारा खर्च की गई अवधि पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा। वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से तृतीय श्रेणी पद

17. उपरोक्त निर्देश के अधीन, डिवीजन बेंच और उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की जाती है। अपील तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निस्तारित की जाएगी। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अंकित ज्ञान

अपील निस्तारित.

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।